



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1744]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2009/कार्तिक 5, 1931

No. 1744]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2009/KARTIKA 5, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2009

तालिका

क्र. सं.	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1.	मंजूसर	1318	0-84-98
2.		1319	0-87-01
3.		1320	0-34-40
4.		1321	0-34-40
5.		1322	0-40-47
6.		1323	0-39-45
7.		1324	0-32-37
8.		1325	0-63-74
9.		1326	0-48-56
10.		1327	0-43-50
11.		1328	0-29-34
12.		1329	0-54-63
13.		1330	0-34-40
14.		1331/ए	0-44-51
15.		133/बी	0-08-09
16.		1332	0-29-34
17.		1333	0-35-41
18.		1334	0-60-70
19.		1335	0-57-67
20.		1336	0-38-45

का. आ. 2706(अ).—यतः, मैं गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो गुजरात राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु एक राज्य संगठन है, ने गुजरात राज्य में बायोटेक पार्क, सावली जी.आई.डी.सी. एस्टेट, ग्राम मंजूसर, जिला वडोदरा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्वारा उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, अब केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 23 जून, 2009 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

1	2	3	4
21.	मंजूसर (जारी)	1339	0-06-07
22.		1340	0-07-08
23.		1341	0-08-09
24.		1342	0-12-10
25.		1343	0-27-32
26.		1344/पी	0-20-44
27.		1349/पी	0-15-76
28.		1350	0-20-23
29.		1351	0-25-29
30.		1352	0-27-32
31.		1353/पी	0-31-10
32.		1354/ए/पी	0-18-48
33.		1354/बी/पी	0-10-12
34.		1408/पी	0-01-26
35.		1409/पी	0-15-84
36.		1410/पी	0-61-06
37.		1619/पी	0-10-56
38.		1620/पी	0-26-40
39.		1621+1622	0-41-48
40.		1623	0-88-03
41.		1624	0-56-65
42.		1625/पी	0-54-74
43.		1627/पी	0-03-50
44.		1629/पी	0-07-20
45.		नल भूमि (सरकारी)	0-83-44
कुल			15-80-98

(ii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 की प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
या उसका नामित जिसका स्तर अवर सचिव,  
भारत सरकार से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय  
क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त  
विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय  
क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क  
आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क  
आयुक्त अथवा उनका नामित जिसका  
स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन

5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय  
क्षेत्राधिकार रखने वाले आयुक्त  
अथवा उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त  
आयुक्त से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग  
प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
7. गुजरात सरकार द्वारा नामित किए जाने  
वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त  
सचिव से कम नहीं होगा —सदस्य, पदेन
8. मै. गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन  
(जोन के विकासकर्ता) का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रित

(iii) केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त क्षेत्र विशिष्ट विशेष जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. 2/489/2006-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2009

S.O. 2706(E).—Whereas M/s. Gujarat Industrial Development Corporation, a state industrial promotion organisation in the State of Gujarat, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for biotechnology sector at Biotech Park, Savli GIDC Estate, Village Manjusar, District Vadodara in the State of Gujarat;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Special Economic Zone on the 23rd June, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :—

(i) the Central Government hereby notifies the following area comprising of the following survey numbers and area given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :—

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.